

बंगाल में भाजपा को प्रचंड जनादेश, असम में हैट्रिक, केरल में कांग्रेस गठबंधन, तमिलनाडु में फिल्म स्टार का जलवा

नई दिल्ली (ए.)। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 202 सीटों के साथ बड़ी जीत की

मोदी की गारंटी, शाह की रणनीति... ममता के भरोसे पर भारी पड़ी भाजपा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है और सत्ताधारी ऑल इंडिया तुणमूल कांग्रेस पर काफी बढ़त बना ली है। इससे राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही 15 सालों से बंगाल में चल रही ममता बनर्जी सरकार का अंत दिख रहा है।

बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पीएम मोदी की गारंटी और अमित शाह की रणनीति की जीत मानी जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई जनसभाएं कीं और राज्य में परिवर्तन का आह्वान किया था। केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने का वादा किया था। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 15 दिनों तक बंगाल में रहे और राज्य के विभिन्न इलाकों में सभाएं कीं और हर विधानसभा सीट के लिए अलग रणनीति बनाई और यह रणनीति अब चुनाव परिणाम में दिख रहा है।

ममता का भरोसा - मोदी की गारंटी

- 3,000 रुपए बनाम 1,500 रुपए और युवाओं पर बड़ा दांव: जहां टीएमसी ने 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया, वहीं बीजेपी ने सीधे दोगुना 3,000 रुपए देने का वादा किया।
- महिलाओं के लिए डबल डोज़: ममता के लक्ष्मी भंडार 1500 के मुकाबले बीजेपी का वादा—हर महिला को 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया। नारी सम्मान को बढ़ा चुनावी हथियार बनाया।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग: टीएमसी पर डीए और वेतन विसंगति का आरोप लगाया। बीजेपी ने 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया।
- 33% महिला आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का वादा: सिर्फ नकद सहायता नहीं, रोजगार में भागीदारी का भी वादा किया।
- यूसीसी का कार्ड: समान नागरिक संहिता—बीजेपी ने इसे

एक कानून, सबके लिए के रूप में पेश किया, जो टीएमसी के नैरेटिव से अलग है।

- घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस: Detect, Delete, Deport—सीमा सुरक्षा और पहचान की राजनीति पर सीधा संदेश दिया और साफ कहा कि घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे।
- कानून-व्यवस्था बनाम कट-मनी: बीजेपी ने भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को विकल्प के रूप में पेश किया।
- उद्योग और सिंगूर पुनर्जीवन: सिंगूर को फिर औद्योगिक हब बनाने का वादा—रोजगार और निवेश का बड़ा संकेत दिया।
- केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ: आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बंगाल में पूरी तरह लागू करने का वादा किया।
- विकसित बंगाल का विजन: टीएमसी के कल्याण मॉडल के मुकाबले बीजेपी ने विकास, निवेश, रोजगार और सुरक्षा का व्यापक ब्लूप्रिंट रखा।

बंगाल में भाजपा का उभार: बीजेपी और अमित शाह की रणनीति की बड़ी बातें

- रणनीति, संयोग नहीं: भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इलेफांट नहीं है। यह नेशनल ज्वाइन और लोकल एक्शन का नतीजा है।
- नेशनल गाइडलाइन, लोकल एक्शन मॉडल: दिल्ली की रणनीति, जमीन पर सटीक क्रियान्वयन—यही पश्चिम बंगाल में गेमचेंजर बना।
- बुध ही असली ताकत: 82,000 में से 71,000 बूथों पर पकड़—चुनाव की बिसात यहीं से पलटी।
- कमिटी मॉडल का माइक्रो मैनेजमेंट: मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़, हर बुध पर संगठन और ग्राउंड कंट्रोल मजबूत किया।
- पुराने कांडर की वापसी: हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना—कोर स्ट्रेंथ को रीबूट किया गया।
- दिल्ली से सीधा कंट्रोल:

अमित शाह की निगरानी में केंद्रीय नेताओं को सीट-वार जिम्मेदारी दी गई। रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए कहा गया।

- आरएसएस का साइडेंट सपोर्ट सिस्टम: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्राइंग रूम मीटिंग्स से घर-घर पहुंच—लो-की, हाई-इम्पैक्ट कैंपेन की गई।
- केडर पर भरोसा, स्टार से दूरी: टॉलीबुड चेहरे और दागी नेताओं से किनारा किया गया। इस बार फोकस सिर्फ अपने संगठन पर रहा।
- सोशल इंजीनियरिंग और कवचल एट्री: पूर्वांचली, मारवाड़ी समाज और लोकल फुटबॉल क्लबों तक पहुंचकर नया वोट बैंक तैयार किया गया।
- नैरेटिव सेटिंग में बदलाव: जय श्री राम, घुसपैठ, महिला सुरक्षा—इन्हें जोड़कर मजबूत वैचारिक फ्रेमवर्क बनाया गया

भाजपा की 'नवीन' नीति ने बदला पश्चिम बंगाल का गणित

नई दिल्ली/ए। बिहार की कुर्सी के बाद अब पश्चिम बंगाल की चाबी। भारतीय जनता पार्टी की 'नवीन नीति' की दूसरी बड़ी सफलता सामने दिख रही है। बिहार में नीतीश कुमार को हटा पहली बार भाजपाई मुख्यमंत्री बनाने के पीछे नए-नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन की कितनी भूमिका थी, इस पर पार्टी में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था और न होगा। लेकिन, जब बात पश्चिम बंगाल की होगी तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के खाले में इसे डालना पड़ेगा।

भाजपा ने 14 दिसंबर को



पटना के बांकीपुर सीट से तत्कालीन विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तभी से यह चर्चा चल निकली थी कि निशाना पश्चिम बंगाल है। 20 जनवरी को जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन बने, तब तक तस्वीर बहुत साफ हो रही थी। फिर बिहार ■ शेष पृष्ठ 6 पर

ओर बढ़ रही है। इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 151 सीट पर बढ़त बनाये हुए है। वहीं असम में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। केरल में यूडीएफ 98 सीटों

के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है, वहीं तमिलनाडु में टीवीके 100 से ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पुडुचेरी में भी एनडीए बहुमत के करीब पहुंच चुका है। बंगाल

में दिग्गज उम्मीदवारों की सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला जारी है। कहीं मुख्यमंत्री आगे हैं तो कहीं बड़े चेहरे पीछे हैं। मतगणना का दौर अभी जारी है।



आंकड़ों में समझिए पांच राज्यों का चुनावी समीकरण					
पश्चिम बंगाल		तमिलनाडु		केरल	
294 सीटें,	बहुमत-148	234 सीटें,	बहुमत-118	140 सीटें,	बहुमत-71
207	भाजपा	108	टीवीके	98	यूडीएफ
79	टीएमसी	72	डीएमके	35	एलडीएफ
02	कांग्रेस	54	एआईएडीएमके	01	बीजेपी
02	सीपीआई	00	अन्य	02	अन्य
असम		निर्वाचन सदन		असम	
126 सीटें,	बहुमत-65	NIRVACHAN SADAN भारत निर्वाचन आयोग LECTION COMMISS OF INDIA		30 सीटें,	बहुमत-16
101	भाजपा गठबंधन			17	भाजपा
21	कांग्रेस गठबंधन			08	कांग्रेस
02	अन्य			05	अन्य

विजय की पार्टी 108 सीटों पर आगे सीएम स्टालिन अपने ही बागी से हारे

दिल्ली (ए.)। असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ताजा रक़्खानों के मुताबिक, तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 2 साल पहले बनी विजय की पार्टी नंबर वन हो गई है। टीवीके ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, 77 सीटों पर आगे चल रही है।

इधर, तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एमके स्टालिन कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें टीवीके के बीएस बाबू ने 8000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बाबू पहले डीएमके में थे। फरवरी 2026 में ही उन्होंने विजय की पार्टी जॉइन की थी। इधर,



टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के साथ बहुमत हासिल करना होगा। एक्टर विजय के पिता चंद्रशेखर ने कहा है कि विजय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इधर,

केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार की वापसी हो रही है। यूडीएफ में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस के गुट शामिल हैं। कांग्रेस 63 सीटें जीत चुकी है।

गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल: मोदी

घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी:

नई दिल्ली/एजेंसी। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा-पश्चिम बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।

महिलाओं को सुरक्षा का महौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनने पर उन्होंने कहा-



गंगोत्री से गंगासागर तक कमल ही कमल खिला है। सालों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूँ।

मोदी के भाषण की खास बातें...

1. ऐतिहासिक जीत और कार्यकर्ताओं का श्रेय: यह दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। सालों की मेहनत आज सफलता में बदली है और इस जीत का पूरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को जाता है।

2. गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल में भाजपा/एनडीए की सरकार है। यानी गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिला है।

3. बंगाल में नई शुरुआत, आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी: बंगाल के भाग्य में नया अध्याय जुड़ा है, राज्य अब भयमुक्त और विकास की ओर बढ़ेगा। यह जीत वंदे मातरम् के 150वें वर्ष में और भी महत्वपूर्ण है। बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा का महौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना को ■ शेष पृष्ठ 6 पर

विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश: साय

रायपुर / नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश जागरूक, राष्ट्रनिष्ठ और विकासोन्मुख जनता की परिपक्व सोच का परिणाम है, जिसने सुशासन, स्थिरता और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को असम और पुडुचेरी में पुनः



जनादेश प्राप्त होना तथा पश्चिम बंगाल में पार्टी की ऐतिहासिक सफलता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित सुशासन और 'विकसित भारत' के संकल्प पर जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने इसे तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और भय की राजनीति ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पीडब्ल्यूडी चौक पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन

मनेंद्रगढ़/नवप्रदेश। बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

प्रदेश कांग्रेस कमेट्री छत्तीसगढ़ के आह्वान और जिला कांग्रेस कमेट्री एमसीबी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी चौक पर महिला कांग्रेस के बैनर तले विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर

जमकर नारेबाजी की।

आम जनता की कमर टूट गई: गुलाब कमरो

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेकाबू महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी कठिन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा



सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक

संघर्ष जारी रखेगी।

रसोई का बजट बिगड़ा, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित

महिला जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) निर्मला चतुर्वेदी और महिला जिला अध्यक्ष (शहरी) रूमा चटर्जी ने संयुक्त रूप से कहा कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ रही है।

रसोई गैस और खाद्य तेलों की कीमतों ने घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि

यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया, तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व नपा उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, पूनम सिंह, ग्रामीण मजूमदार, बलवीर सिंह, दीपक श्रीवास्तव, राजा पांडे, विवेक चतुर्वेदी, सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न्यूज गैलरी

कछिया की सरपंच-गांव के बच्चों के लिए एक माँ जैसी जिम्मेदारी



बलरामपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले में एक ऐसी महिला का सम्मान किया जो दिल को छू गया।जनपद पंचायत वाइज़मनगर के अंतर्गत ‘ग्राम पंचायत कछिया’ की सरपंच’ खुशबू सिंह’ और सचिव सुनीता मरावी’ को मुख्यमंत्री ने शीलड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस छोटे से गांव ने पीएआई 2.0 सर्वे में ‘प्रदेश भर में बाल हितैषी पंचायत’ की श्रेणी में 95.71 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि बताती है कि जब एक गांव की महिला नेतृत्व में आती है, तो वह सबसे पहले बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करती है।

कीमत में बढ़ोतरी: सिलेंडर को माला पहना जताया विरोध

जांजगीर/नवप्रदेश। जांजगीर-चांपा में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध के अनोखे तरीके से गैस सिलेंडर पर फूल-माला चढ़ाकर उसे ‘श्रद्धांजलि’ दी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि फरवरी से अब तक व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में करीब 1300 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है और हाल में 993 रुपए बढ़ाना आम जनता व व्यापारियों पर बोझ है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ाना गलत है। विधायक ब्यास कश्यप ने साधा निशाना: विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि गैस की कीमत बढ़ने से रोममर्रा की चीजें महंगी होंगी और इसका असर मध्यम व गरीब वर्ग पर पड़ेगा। इससे कहा कि पहले गैस 400 रुपए होने पर विरोध करने वाले नेता अब चुप हैं। जल्द कीमतें कम नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

मवेशी तस्करों से बचाई गई 15 भैंसों, 5 गिरफ्तार

जांजगीर/नवप्रदेश। अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवरीनारायण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरराज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 15 भैंसों और तस्करी में प्रयुक्त तीन पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 20 लाख 25 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, रविवार की सुबह 5 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन पिकअप वाहनों में मवेशियों को कूरातापूर्वक भरकर ओडिशा के बूचड़खानों की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना शिवरीनारायण पुलिस ने टीम गठित कर मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की। शिवरीनारायण के राघव इन होटल के सामने तीन संदिग्ध पिकअप वाहनों को रोका गया। जांच के दौरान प्रत्येक वाहन में 5-5 भैंसों को रस्सियों से बांधकर ट्रंस-ट्रंस कर भरा गया था। पुलिस ने मौके से ओडिशा के बरागढ़ जिले के पांच मुकेश ऐंडजा (26), राजेश माझी (26), निरंजन कोलारी (25), रूपेश कुमार (20) और प्रकाश राणा (32) को गिरफ्तार किया है। जब्त मवेशियों की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए और तीनों वाहनों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। पछताछ में आरोपियों ने मवेशियों को ओडिशा ले जाकर तस्करी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

50 लाख से बनेगा प्रेस क्लब भवन वित्त मंत्री चौधरी ने किया भूमिपूजन

रायगढ़/नवप्रदेश। शहर के पत्रकारों को बहुप्रतीक्षित प्रेस क्लब भवन की सीगात मिली है। वित्त मंत्री व विधायक ओपी चौधरी ने वाई क्रमांक 27 में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रेस क्लब सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। इसमें 20 लाख रुपए शासन से और 30 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के लगातार प्रयास से यह काम शुरू हो सका है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता से समझौता न करने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। भवन को इस तरह डिजाइन करने की बात कही गई है, जिससे भविष्य में प्रथम तल का विस्तार किया जा सके। परिसर में पार्किंग, गार्डन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित कर इसे सुव्यवस्थित कैम्पस के रूप में तैयार किया जाएगा। मुख्य मार्ग के संभावित कंड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए निर्माण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महापौर जीवर्धन चौहान ने इसे पत्रकारों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

अवैध वसूली व पेड़ों की कटाई के आरोपों में घिरे उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

सरपंच सहित 14 में से 12 पंचों ने पारित किया अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत में मचा राजनीतिक भूचाल

सकरी/नवप्रदेश। ग्राम पंचायत जोकि में उप सरपंच अशोक यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सरपंच सहित कुल 14 पंचों में से 12 पंचों ने उप सरपंच को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। इस फैसले के बाद पंचायत की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, उप सरपंच अशोक यादव पर ग्राम में अवैध वसूली, शासकीय पेड़ों की अवैध कटाई और मनमानी तरीके से कार्य करने जैसे गंभीर आरोप लंबे समय से लगाए जा रहे थे। पंचों का कहना है कि इन मुद्दों को लेकर कई बार बैठकें आयोजित की गईं और उप



सरपंच को सुधार का मौका भी दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

बताया जा रहा है कि इन आरोपों से नाराज होकर पंचायत के अधिकांश पंच एकजुट हो गए

और अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचायत भवन में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरपंच की मौजूदगी में मतदान कराया गया। मतदान के दौरान 14 में से 12

पंचों ने उप सरपंच के खिलाफ वोट करते हुए प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया।

बैठक के दौरान पंचायत परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण

भी मौजूद रहे। प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे प्रशासन को भेज दिया गया है, जहां नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो उप सरपंच को पद से

सांसद महंत की पहल पर अब खोंगापानी बस स्टॉप पर बसों का ठहराव अनिवार्य

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी/नवप्रदेश। खोंगापानी नगर पंचायत क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद, जिला परिवहन विभाग ने खोंगापानी बस स्टॉप पर सभी बसों के रुकने को अनिवार्य कर दिया है। अब यात्रियों को बस पकड़ने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

हाल ही में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत ने इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया था कि बस चालक खोंगापानी स्टॉप पर बसें नहीं रोक्ते, जिससे स्थानीय नागरिकों और दैनिक यात्रियों

को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सांसद के निर्देश पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन अधिकारी (कोरिया) ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

अनिवार्य ठहराव: सभी स्टेज कैरिज बसों को खोंगापानी के निर्धारित बस स्टॉप पर रुकना होगा।

यात्री सुविधा: चालक और परिचालक को यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

दंडात्मक कार्रवाई: निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों और परमिट धारकों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम: कमरो

गुलाब कमरो, पूर्व विधायक (भरतपुर-सोनहत) ने कहा कि यह निर्णय आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यात्रियों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है और क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी।

जनता में हर्ष की लहर

सांसद की इस सक्रियता से खोंगापानी क्षेत्र के नागरिकों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सांसद ज्योत्सना महंत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आदेश के बाद अब बसों के इंतजार में खड़े यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

बाइक प्रवेश द्वार से टकराई, युवक की मौत

जांजगीर/नवप्रदेश। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सेमरा में सड़क हादसे में 25 साल के संतोष कुमार साहू की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक गांव के प्रवेश द्वार से टकरा गई, जिससे युवक को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार ग्राम मुड़पार निवासी

संतोष कुमार साहू अपनी बाइक से ससुराल ग्राम किरात जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण वह अनियंत्रित हो गई। बाइक सीधे गांव के स्वागत द्वार से जा टकराई, जिससे बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के सिर पर

गंभीर चोट लगी, जिससे 2 इंच से अधिक गहरा घाव हो गया और आंख बाहर आ गई। हादसे की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी अस्पताल नवागढ़ भेजा है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करारक उन्हें सौंप दिया जाएगा।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी/नवप्रदेश।

जिले के केलहारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिहुली में भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल 38 वर्षीय युवक तिग्गा को मनेंद्रगढ़ के 220 बिस्तर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है। 28 अप्रैल की सुबह करीब 6:30 बजे जब युवक घर के पास जंगल किनारे गया था, तब भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलहारी पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल मनेंद्रगढ़ रेफर कर दिया गया।

अस्पताल में डॉ. अलेख सिदार (ईएनटी विशेषज्ञ) और डॉ. इंतजार ओरके (अस्थि रोग विशेषज्ञ) के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने करीब 5 घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के बाद युवक की जान बचाने में सफलता हासिल की। इस सर्जरी में अभिषेक, प्रियंका और पुष्पा सहित नर्सिंग स्टाफ की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थानीय स्तर पर मिली बड़ी राहत

हाल ही में 220 बिस्तर में



उन्नत हुए इस अस्पताल में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन और अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी के प्रबंधन में चिकित्सकों ने मरीज को बाहर रेफर करने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही उपचार करने का निर्णय लिया। इस सफलता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूरी मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाओं से आम जनता का

विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा है।

आधुनिक सुविधाओं का विस्तार

अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार की कड़ी में अब इंडोस्कोपी यूनिट भी तैयार हो चुकी है, जिससे क्षेत्रवासियों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रशासन ने जंगली क्षेत्रों से लगे ग्रामीणों को अकेले जंगल की ओर न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

संगठन में हुई शिकायत, जिला पंचायत में भाजपा के भीतर बगावत से मचा सियासी भूचाल

जिला पंचायत में भाजपा समर्थित सदस्यों ने की अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत

जांजगीर चाम्पा/नवप्रदेश। जिला पंचायत में भाजपा समर्थित सदस्यों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां अपने ही दल के खिलाफ गतिविधियों से संगठन में असंतोष खुलकर सामने आ गया है, मामले की शिकायत वरिष्ठ नेताओं तक पहुंची है और अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संगठन से मांग की है कि ऐसे बगावती सदस्यों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पार्टी की गरिमा बनी रहे, अब देखना होगा कि भाजपा संगठन अपने ही सदस्यों के खिलाफ क्या कदम उठाता है और इस

अंदरूनी विवाद को कैसे सुलझाता है।

कांग्रेस से सांतगांठ का आरोप

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई सदस्यों ने संगठन के वरिष्ठ नेताओं से औपचारिक शिकायत की है कि कुछ सदस्य लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे संगठन की छवि नुकसान पहुंच रहा है और अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ सदस्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर भाजपा और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, सोशल



मीडिया पर अपने निजी मोबाइल नंबरों से ऐसे स्टेटस डाले गए जिनमें वोट खरीदने और पैसे के लेनदेन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है

बड़े नेताओं पर लगाए आरोप

जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा नेताओं पर भी इन सदस्यों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, उन्हें धोखा

देने वाला बताकर सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया गया, जिससे पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिला पंचायत की सामान्य सभा में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही अपनी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना और 29 मई को निंदा प्रस्ताव के विरोध में अध्यक्ष कक्ष के बाहर धरना देना, अनुशासनहीनता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, साथ ही कांग्रेस विधायक के साथ मिलकर चक्का जाम करने और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

विपक्ष ले रहा चुटकी, क्षेत्र में बन रहा मजाक का माहौल

जिला पंचायत के भीतर चल रही इस खींचतान का असर अब राजनीतिक गलियारों में भी दिखने लगा है क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़े लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों द्वारा कहा गया कि जिला पंचायत में चुने गए भाजपा के प्रत्याशी अपने ही संगठन में दो गुटों में बंटे हुई हैं और आपसी संतुलन तक नहीं बना पा रही है बताया जा रहा है कि इस अंदरूनी विवाद के चलते विपक्ष की बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिससे राजनीतिक माहौल में भाजपा की किरकिरी होती नजर आ रही है।

किसानों को उनका वैभव लौटाने का लिया गया है संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

27,746 करोड़ के पैकेज से आय बढ़ेगी और घटेगी लागत

सिंचाई 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगी

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मिशन मोड में लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

यादव ने कहा कि इस पूरे वर्ष किसानों को उनका वैभव लौटाने का संकल्प लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, कृषि लागत को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके लिए 16 विभाग एक साथ समन्वय से काम कर रहे हैं। विगत दिनों बड़वानी में हुई कृषि कैबिनेट में 27,746 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना

सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। आय में वृद्धि के लिए दूध, फल, सब्जी और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ अन्य स्रोतों से भी कमाई के अवसर मिलेंगे। लागत में कमी लाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा और मिट्टी परीक्षण के जरिए संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देकर अनावश्यक खर्च घटाया जाएगा।

तकनीक और विपणन के क्षेत्र में किसानों को अंकीय सेवा, कृषि प्रसंस्करण, कृषि-तकनीक, ड्रोन सेवा और किसान उत्पादक संगठन प्रबंधन से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए जल-कृषि जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सिंचाई क्षमता को विस्तार देने के लिए वर्तमान में 65 लाख हेक्टेयर के सिंचित क्षेत्र को वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने

का लक्ष्य तय किया गया है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में कृषि विभाग 3,502.48 करोड़ रुपये की 20 परियोजनाओं को 31 मार्च 2031 तक चलाएगा। इसके तहत उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती और फसल प्रदर्शन योजनाएं संचालित होंगी। मृंग की जगह उड़द उत्पादन पर किसानों को 600 रुपये प्रति किंटल बोनस दिया जाएगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। रोटावेटर आधी

कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग 9,508 करोड़ रुपये की 4 योजनाओं से दूध संकलन 25 प्रतिशत तक बढ़ाएगा। पशुपालकों को मोबाइल ऐप से सेवाएं मिलेंगी और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 610.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,263.94 करोड़ रुपये की 3 योजनाओं पर काम करेगा। राष्ट्रीय

उद्यानिकी मिशन के लिए 1150 करोड़ रुपये और पौधशाळा उद्यान के लिए 1,739 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता की पौध और बीज रियायती दरों पर मिलेंगे। सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रुपये से नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग 218.50 करोड़ रुपये की 2 योजनाएं चलाएगा।

न्यूज़ गैलरी

एमपी ट्रांसको ने जुलवानिया सब स्टेशन में ऊर्जीकृत किया 40 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर : ऊर्जा मंत्री तोमर



भोपाल/नवप्रदेश। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने बड़वानी जिले की ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए 220 केवी सब स्टेशन जुलवानिया में 40 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किया है। इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से बड़वानी जिले की ट्रांसफार्मेंसन कैपेसिटी बढ़कर 2642 एमवीए की हो गई है, वहीं जुलवानिया सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर 423 एमवीए की हो गई है। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि जुलवानिया 220 केवी सब स्टेशन में वर्तमान और भविष्य में बढ़ते लोड को देखते हुए 20 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर दुगुनी क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किया गया है। इस क्षमता वृद्धि से जुलवानिया से जुड़े हजारों घरेलू, कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा अब उन्हें और अधिक गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध रहेगी।

छह फीसों के माध्यम से होती है विद्युत आपूर्ति

एमपी ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता श्री सुरेंद्र सोलंकी ने बताया की 220 केवी सब स्टेशन जुलवानिया से 33 केवी के छह फीडरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इनमें राजपुर, सेंधवा, नागलवाड़ी, मनवाड़ा, जुलवानिया एवं सेगांव शामिल हैं।

बड़वानी जिले में एमपी ट्रांसको के 9 सब स्टेशन

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी बड़वानी जिले में अपने 9 सब स्टेशनों के माध्यम से विद्युत पारेषण करती है जिनमें 400 केवी जुलवानिया की क्षमता 1490 एमवीए, 220 केवी के दो सब स्टेशन जुलवानिया 423 एमवीए एवं सेंधवा 223 एमवीए एवं 132 केवी के 6 सब स्टेशन सेंधवा 113 एमवीए, शाहपुरा 40 एमवीए, बड़वानी 123 एमवीए, पानसेमल 90 एमवीए, पाटी 50 एमवीए, अंजड 90 एमवीए की ट्रांसफार्मेंशन क्षमता शामिल हैं, जिनकी कुल ट्रांसफारेमेशन क्षमता 2642 एमवीए की है।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही



उज्जैन एवं इंदौर में 1 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की शराब, बियर व वाहन जप्त

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन एवं इंदौर में दो अलग-अलग कार्रवाईयों में लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब, बीयर एवं वाहन जप्त किए हैं।

उज्जैन

जिले के नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत निनोरा टोल प्लाजा के पास पुलिस ने घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 900 पेट्टी (21,600 केन) कुल 10,800 बल्क लीटर अवैध बीयर परिवहन की जा रही थी। जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये है, तथा परिवहन में प्रयुक्त ट्रक (कीमत लगभग 55 लाख रूपये) को जप्त किया । इस प्रकार लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जन्त की है। प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

इंदौर

जिले में वाहन चेंकिंग के दौरान एक कार से 43 पेट्टी अवैध अंग्रेजी शराब जन्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रूपये है। मध्यप्रदेश पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

तोमर ने उप नगर ग्वालियर के वार्ड 17, 6 और 7 में किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनसुविधा से जुड़ी समस्याओं में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल/नवप्रदेश। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रविवार को उप नगर ग्वालियर के वार्ड 17, 6 तथा 7 में विभिन्न गली-मोहल्लों की सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनसुविधा से जुड़ी क्षेत्रवासियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्य सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी कि सीवर की सफाई, कचरा संग्रहण और सड़कों के रखरखाव के कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने आमजन की सीवर, पानी, बिजली तथा सड़क से सम्बन्धित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्वालियर विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार को कोई भी असुविधा न



हो मूलभूत सुविधाओ में जो कमी है, उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। उन्होंने रविवार की सुबह 6 बजे उप नगर ग्वालियर के वार्ड 17 स्थित विभिन्न गली, मोहल्लों में पेयजलापूर्ति, सीवर सफाई, बिजली व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। उप नगर ग्वालियर के वार्ड 06 स्थित जहाँगीर कटरा,मेवाती मोहल्ला, लधेडी, जगना पुरा, हथियापौर तथा वार्ड 7 के श्रीकृष्ण नगर में भी पहुंचे तथा यहां चल रही सरकार की विभिन्न

जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों से जानकारी ली। उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बन गया है। इसके जवाब में लोगों अपनी सहमति जताई। उन्होंने बहनों तथा बुजुर्ग माताओं से बातचीत कि और उनसे कुशलक्षेम पूछी।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हर कदम पर एक ही भावना रहनी चाहिए, हम बदलेंगे, तो हमारा ग्वालियर बदलेगा। यह राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक

संकल्प है, अपने शहर, अपनी पीढ़ी और अपनों के भविष्य के लिए। उन्होंने आव्हान किया कि ग्वालियर को स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने के अपने संकल्प को जनसहभागिता के साथ सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाना है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनसुविधा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनता की सेवा और समस्याओं का समयबद्ध समाधान आपके सेवक की प्राथमिकता है।

6 साल बाद महिला आयोग को अध्यक्ष मिला, रेखा यादव को सौंपी कमान

नाम तय होने के बावजूद अटका था फैसला

भोपाल/नवप्रदेश। करीब छह साल के इंतजार के बाद मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है। सरकार ने रेखा यादव को अध्यक्ष और साधना स्थापक को सदस्य नियुक्त करते हुए आयोग को फिर सक्रिय कर दिया है। मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद राज्य महिला आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है। सरकार ने आयोग के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेखा यादव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साधना स्थापक को आयोग का सदस्य



बनाया गया है, जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है। करीब छह साल के अंतराल के बाद आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होने से इसे महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। बता दें रेखा यादव का नाम महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए तय हो गया था, लेकिन उनके नाम

को लेकर आपत्ति आने के बाद उसे होल्ड कर दिया गया था। अब सरकार ने उनके नाम पर ही मुहर लगा दी है। प्रदेश में इन दिनों निगम, मंडल, आयोग और विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों का दौर तेज है। अब तक करीब दो दर्जन से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि शेष रिक्त पदों को भी भरने की

प्रक्रिया लगातार जारी है। महिला आयोग को अध्यक्ष और सदस्य मिलने से प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और नीतिगत फैसलों को नई गति मिलेगी। लंबे समय से आयोग में शीर्ष पद खाली होने के कारण कई मामलों में निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। बता दें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद जनवरी 2019 के बाद से स्थायी रूप से नहीं भरा जा सका है। बीच में 2020 में कांग्रेस की सरकार बनने पर शोभा ओझा की नियुक्ति की गई, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद उन्होंने आयोग की सभी को हटा दिया। इसके बाद लंबे समय तक मामला कोर्ट में चला।

हज की व्यवस्थाओं पर भारतीयों ने जताई नाराजगी: 4 लाख खर्च

फिर भी बदइंतजामी; हाजी इमरान हारून बोले- निष्पक्ष जांच जरूरी

भोपाल/नवप्रदेश। हज यात्रा से पहले ही मक्का में भारतीय हाजियों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल एक वीडियो में हाजियों ने ठहरे, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। इसे लेकर मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने केंद्रीय हज कमिटी से तत्काल संज्ञान लेकर वीडियो की



सत्यता की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक हज के लिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। इस बार भी मक्का के

अज़ीज़िया क्षेत्र से जो वीडियो सामने आया है, उसमें हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं।

एक कमरे में कई लोगों को ठहराया

वायरल वीडियो में हाजी कमरों की स्थिति दिखाते रहे हैं। वे

कह रहे हैं कि उन्हें बेहद खराब हालात में रखा है। एक कमरे में कई लोगों को ठहराया है। वॉशरूम गंदे हैं, जिसका गंदा पानी कमरों तक पहुंच रहा है। लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। हाजियों ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शिकायत के मुताबिक अज़ीज़िया स्थित एक हॉस्टल में एक कमरे में 16 लोगों को ठहराया गया था। परिवारों को अलग-अलग रखा गया। एक ही वॉशरूम का उपयोग कई लोग कर रहे हैं। साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद खराब है।

भोपाल में किसानों का एसडीएम ऑफिस के बाहर डेरा



गेहूं की स्लॉट बुकिंग, सीमांकन जैसे मामलों पर नाराजगी; जमीन अधिग्रहण का भी विरोध

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल के कई किसानों ने एमपी नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर डेरा डाल लिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की स्लॉट बुकिंग, सीमांकन, नामांकन जैसे मामलों को लेकर उनकी नाराजगी है। वहीं, सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण का विरोध भी वे कर रहे हैं।

एमपी नगर और हुजूर तहसील के किसानों ने डेरा डाला है। किसान कुबैर सिंह राजपूत ने बताया कि एमपी नगर व हुजूर तहसील के किसानों को तहसील से जुड़ी कई समस्याएं आ रही हैं। इनमें गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग, किसान सम्मान निधि, फार्मर आईडी नहीं बनाना, सीमांकन, नामांतरण, बंटान, बिजली, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण आदि शामिल हैं।

राजस्व प्रकरणों में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने तहसील हुजूर ने कई बार आवेदन दिए। बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए एमपी नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

पटवारी सोमवार और गुरुवार को गांव में बैठे

किसानों की मांग है कि पटवारियों को हर सोमवार और गुरुवार को संबंधित हल्के के गांवों में बैठना चाहिए। ताकि, किसानों को पेशानी न हो और उन्हें तहसील या जिला मुख्यालय के चक्र नहीं लगाने पड़ें।

ऐसे समझे किसानों की पेशानी

गेहूं खरीदी में देरी और

अव्यवस्था- सबसे बड़ी समस्या सरकारी गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खरीदी में देरी और पोर्टल की खराबी है। स्लॉट बुकिंग न होना के कारण अव्यवस्था से किसानों का गेहूं खेतों में या घरों में पड़ा है। जिससे खराब मौसम में नुकसान का डर है।

भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा: पिपलानी बी-सेक्टर से खजुरीकलां बायपास तक 4 लेन रोड निर्माण कार्य प्रोजेक्ट लंबाई- 4.2 किमी के अंतर्गत आने वाले किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देने की मांग है। वे रजिस्ट्री के %छठ बिन्नी पत्र%, अधिकतम बाजार मूल्य की रजिस्ट्री, जमीन के भविष्य के उपयोग, क्षेत्र में हो रहे विकास एवं आगामी वर्षों में उक्त भूमि की संभावित कीमत के आधार पर बाजार मूल्य से 4 गुना कीमत के आधार पर शीघ्र मुआवजा देने की बात कर रहे हैं।

ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश: कटाई के समय होने वाली बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए शीघ्र सर्वे कराकर पारदर्शिता सुनिश्चित कर लाभ दिया जाए।

समय सीमा तय किया जाना सुनिश्चित - तहसील एमपी नगर के किसानों के नामांतरण, बंटोकन, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में नहीं हो रहा है। यहां पर बाबूवाद भी हावी है। कई बार दत्तालों के माध्यम से ही काम किया जाता है। बिजली के तार व पोल में सुधार : बिजली कंपनी की लापरवाही के चलते लाइन के तार और पोल को लेकर भी धिक्कतें हैं। कई जगहों से लाइन डेमेज हो गई है। बारिश से पहले इनका संधारण किया जाए।

क्या निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को नर्मदा जल की नियमित आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्यास को पानी पिलाना हमारी संस्कृति में पुष्प का कार्य माना गया है और इसी भावना के साथ क्षेत्र के नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की गई है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नई पानी की टंकियों का निर्माण आवश्यक हो गया था। अमृत फेस-2 योजना के अंतर्गत क्षेत्र में कुल 18 टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में जल संकट की समस्या से राहत मिलेगी।

मिसरोद और बरखेड़ा पठानी में 2 करोड़ 70 लाख की लागत से होगा पानी की टंकियों का निर्माण

राज्यमंत्री गौर ने ढाई लाख और दो लाख लीटर की क्षमता वाली टंकियों का किया भूमिपूजन

भोपाल/नवप्रदेश। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने रविवार को गोविंदपुरा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2 पानी की टंकियों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर की इस पहल से मिसरोद स्थित फॉर्च्यून डिव्हाइन सिटी के पास 2.5 लाख लीटर क्षमता तथा प्रताप नगर, बरखेड़ा पठानी के पास 2 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकियों की स्थापना होगी। 2 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत से इन टंकियों

